



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

No. 193]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

गृह मंत्रालय

(सीएस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 297(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध बहरीन अधिराज्य की सरकार पर लागू होंगे। भारत गणराज्य की सरकार तथा बहरीन अधिराज्य की सरकार द्वारा दंडित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में दिनांक 23.01.2016 को हस्ताक्षरित करार का सम्पूर्ण पाठ नीचे दिया गया है। भारत गणराज्य की सरकार द्वारा दिनांक 10.03.2017 को और बहरीन अधिराज्य की सरकार द्वारा दिनांक 18.05.2017 को इस करार का अनुसमर्थन किया गया।

## दंडित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार तथा बहरीन अधिराज्य की सरकार के बीच करार

भारत-गणराज्य तथा बहरीन अधिराज्य, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकार देश कहा गया है;

दंडित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से; और

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य, कोई दांडिक अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दंडित किए गए विदेशी नागरिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सज़ा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गए हैं :

**अनुच्छेद 1****परिभाषाएं**

इस करार के प्रयोजन के लिए:

- (क) “निर्णय” से तात्पर्य दंड देने वाले न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी निर्णय अथवा आदेश से है;
- (ख) “निष्पादनकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसमें दंडित व्यक्ति को सज़ा अथवा शेष सज़ा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) “दंड” से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा अपने दांडिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आदेशित स्वतंत्रता से संचित रखे जाने का कोई दंड या उपाय है;
- (घ) “दंडित व्यक्ति” से तात्पर्य किसी दांडिक न्यायालय, जिसमें संविदाकार देशों में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित न्यायालय भी शामिल हैं, द्वारा पारित किसी निर्णय के तहत कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति से है।
- (ङ) “दंडदाता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जा सकता है या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

**अनुच्छेद 2****सामान्य सिद्धांत**

1. इस करार के प्रावधानों के अनुसार किसी एक संविदाकार देश के भू-भाग में दंडित किसी व्यक्ति को उसे दी गई सज़ा काटने के लिए दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है। इस संबंध में, दंडित व्यक्ति इस करार के अंतर्गत दंडदाता देश अथवा निष्पादनकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।
2. अंतरण का अनुरोध किसी दंडित व्यक्ति द्वारा, जो किसी संविदाकार देश का नागरिक है अथवा संविदाकार देशों के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, संविदाकार देश को और उक्त संविदाकार देश की सरकार द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से आवेदन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

**अनुच्छेद 3****केन्द्रीय प्राधिकारी**

1. संविदाकार देशों के लिए इस करार के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी केन्द्रीय प्राधिकारी निम्नलिखित हैं :
  - भारत गणराज्य के लिए : गृह मंत्रालय
  - बहरीन अधिराज्य के लिए : न्याय, इस्लामिक कार्य और वक्फ मंत्रालय
2. यदि कोई संविदाकार देश अपना केन्द्रीय प्राधिकारी बदलता है, तो वह दूसरे देश को राजनयिक चैनलों के माध्यम से इसके बारे में अधिसूचित करेगा।

**अनुच्छेद 4****अंतरण की शर्तें**

1. इस करारके अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अंतरित किया जा सकता है :
  - (क) वह व्यक्ति निष्पादनकर्ता देश का नागरिक हो;
  - (ख) दंडित व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया गया हो;
  - (ग) निर्णय अंतिम हो ;

- (घ) दंडदाता देश में दंडित व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही लम्बित नहीं हो जिसमें उसकी उपस्थिति अपेक्षित है;
- (ङ.) दंडित व्यक्ति को सैन्य कानून के तहत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो;
- (च) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय, दंडित व्यक्ति को अभी भी कम से कम छः माह की सज़ा काटनी हो अथवा वह आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा हो;
- (छ) यह कि व्यक्ति को दंडदाता देश में जिन कृत्यों अथवा चूकों के लिए दंड दिया गया था, वे निष्पादनकर्ता देश में अपराध के रूप में दंडनीय हों, अथवा यदि उसके अपने भू-भाग में किए जाते तो दांडिक अपराध होते;
- (ज) निष्पादनकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से दंडदाता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;
- (झ) अंतरण के संबंध में दंडित व्यक्ति द्वारा लिखित में सहमति दी गई हो अथवा, दंडित व्यक्ति की आयु अथवा शरीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर दोनों में से किसी संविदाकार देश द्वारा जरूरी समझे जाने पर, संविदाकार देश के कानून के अनुसार उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और
- (ञ) दंडदाता और निष्पादनकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।
2. आपवादिक मामलोंमें, दंडदाता एवं निष्पादनकर्ता देश अंतरण के लिए सहमत हो सकते हैं चाहे दंडित व्यक्ति द्वारा काटी जाने वाली सज़ा की शेष अवधि छह माह से कम हो।

### **अनुच्छेद 5**

#### **सूचना मुहैया करवाने की बाध्यता**

1. यदि दंडित व्यक्ति ने दंडदातादेश को इस करार के तहत अंतरित होने की इच्छा व्यक्त की हो तो, दंडदाता देश निष्पादनकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज़ भेजेगा जब तक कि निष्पादनकर्ता या दंडदाता देश में से किसी के भी द्वारा पहले ऐसा कोई निर्णय ल लिया गया हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं है :
- (क) दंडित व्यक्ति का नाम एवं राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान और निष्पादनकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो, और साथ ही उसके पासपोर्ट या अन्य व्यक्तिगत पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रति और फिंगरप्रिंट, जो भी संभव हो;
- (ख) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दंड आधारित था;
- (ग) दंड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
- (घ) निर्णय की प्रमाणित प्रिंट तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के खिलाफ दंड पारित किया गया है;
- (ङ) दंडित व्यक्ति की कोई चिकित्सीय, सामाजिक अथवा दंडित व्यक्ति के पूर्ववृत्त तथा चरित्र के बारे में अन्य कोई रिपोर्ट, जहां उसके आवेदन का निपटान करने अथवा उसके कारावास की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए यह अपेक्षित हो;
- (च) यथा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी जिसे निष्पादनकर्ता देश विनिर्दिष्ट करे कि यह संबंधित मामले में अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके;

(छ) अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्ति अथवा दंडदाता देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति का अनुरोध;

(ज) यह दर्शाने वाला विवरण कि कितनी सज़ा पहले ही पूरी कर ली गई है तथा विचारण-पूर्व नजरबंदी, क्षमा अथवा दंड के प्रवर्तन के बारे में सूचना; और

2. इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से निष्पादनकर्ता देश दंडदाता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज़ भेजेगा जब तब कि निष्पादनकर्ता या दंडदाता देश ने पहले ही यह निश्चय न कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं होगा:

(क) एक विवरण अथवा दस्तावेज़ जो यह दर्शाता हो कि दंडित व्यक्ति निष्पादनकर्ता देश का एक नागरिक हो;

(ख) निष्पादनकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें यह प्रावधान हो कि ऐसे कृत्य अथवा चूकें जिनके कारण दंडदाता देश में इस प्रकार से दंड पारित किया गया है, निष्पादनकर्ता देश के कानून के अंतर्गत अपराध हों अथवा यदि, ऐसे कृत्य अथवा चूकें इसके भू-भाग में घटित हुई होती तो वे अपराध होती।

(ग) दंडित व्यक्ति के अंतरण पर इस करार के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव का विवरण, यदि लागू हो, के सहित उसके अंतरण के बाद निष्पादनकर्ता देश में दंड की अवधि एवं प्रवर्तन संबंधी किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;

(घ) दंडित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए निष्पादनकर्ता देश की इच्छा और दंडित व्यक्ति की सज़ा के बाकी बचे हिस्से को लागू करने हेतु एक बचनबद्धता; तथा

(ङ.) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज़ जिसे दंडदाता देश आवश्यक समझे।

### **अनुच्छेद 6**

#### **अनुरोध एवं जवाब**

1. अंतरण के लिए अनुरोध निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई हो, में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और राजनयिक माध्यम के द्वारा दंडदाता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से निष्पादनकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा। जवाब उन्हीं माध्यमों से संसूचित किए जाएंगे।

2. निष्पादनकर्ता देश शीघ्रतापूर्वक दंडदाता देश को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह प्रार्थित अंतरण के लिए सहमत है अथवा नहीं।

### **अनुच्छेद 7**

#### **सहमति और इसका सत्यापन**

1. दंडदाता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 4 के पैरा 1 (i) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है। इस प्रकार की सहमति देने की प्रक्रिया दंडदाता देश के कानून द्वारा शासित होगी।

2. दंडदाता देश, निष्पादनकर्ता देश को यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि सहमति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है।

### **अनुच्छेद 8**

#### **निष्पादनकर्ता देश के लिए अंतरण का प्रभाव**

1. निष्पादनकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी, इस करार के अनुच्छेद 9 में निर्धारित शर्तों के अधीन किसी न्यायालय आदेश अथवा प्रशासनिक आदेश, जैसा भी उसके राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपेक्षित होगा, के माध्यम से दंड के प्रवर्तन को जारी रखेंगे।

2. इस करारके अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के अध्वधीन, दंड का प्रवर्तन निष्पादनकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा और सिर्फ वही देश समस्त समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

### **अनुच्छेद 9**

#### **सज़ा का सतत् प्रवर्तन**

1. निष्पादनकर्ता देश, दंडदाता देश द्वारा यथा-अवधारित सज़ा की कानूनी प्रकृति एवं अवधि से आवद्ध होगा।
2. यदि दंड की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनों ही निष्पादनकर्ता देश के कानून से असंगत हों, तो वह देश, दंडदाता देश की पूर्व सहमति से न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा दंड को इसी प्रकार के अपराध के लिए अपने स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित दंड अथवा उपाय के अनुरूप बना सकेगा। जहां तक इसकी प्रकृति एवं अवधि का प्रश्न है, रुपान्तरित दंड यथासंभव, दंडदाता देश के निर्णय द्वारा दिए गए दंड के अनुरूप होगा। तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा दंडदाता देश में दिए गए दंड में वृद्धि नहीं करेगा।

### **अनुच्छेद 10**

#### **दंडदाता देश के लिए सज़ा के समापन का प्रभाव**

जब निष्पादनकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1 (क) के तहत दंडदाता देश को यह अधिसूचित करता है कि दंड पूरा हो गया है, तो ऐसी अधिसूचना दंडदाता देश में उस दंड को पूरा करने करने के संबंध में प्रभावी मानी जाएगी।

### **अनुच्छेद 11**

#### **निर्णय और माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण की समीक्षा**

1. दंडदाता देश निर्णय की पुनरीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेगा।
2. कोई भी संविदाकार देश दंडदाता देश से परामर्श करने के बाद अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दंड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दंड का लघुकरण कर सकेगा।

### **अनुच्छेद 12**

#### **दंड के प्रवर्तन की समाप्ति**

1. दंडदाता देश अपने भू-भाग में लिए गए किसी भी निर्णय की सूचना तुरंत निष्पादनकर्ता देश को देगा जिसके लिए सज़ा या उसके भाग के प्रवर्तन को समाप्त करना आवश्यक होगा।
2. जैसे ही दंडदाता देश द्वारा किसी भी ऐसे निर्णय अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड का प्रवर्तन समाप्त हो गया हो, तो निष्पादनकर्ता देश दंड या उसके भाग के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

### **अनुच्छेद 13**

#### **दंड के प्रवर्तन संबंधी सूचना**

1. निष्पादनकर्ता देश दंडदाता देश को अधिसूचित करेगा :
  - (क) जब दंड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा
  - (ख) यदि दंड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में निष्पादनकर्ता देश को चाहिए कि वह दंडित व्यक्ति की गिरफ्तारी का हर-संभव प्रयास करे ताकि वह उसको मिले दंड के शेष भाग को पूरा करा सके और निष्पादनकर्ता देश के संगत कानून के अन्तर्गत कारित अपराध के लिए कैदी को उत्तरदायी ठहराया जा सके।
2. निष्पादनकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

**अनुच्छेद 14****पारगमन**

1. यदि कोई भी संविदाकार देश दंडित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है, तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्तियों के पारगमन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा सिवाय इसके कि वह निम्नलिखित स्थिति में पारगमन से इन्कार कर सकता है:-

(क) यदि दंडित व्यक्ति उसका अपना नागरिक हो।

(ख) यदि अनुरोध से संविदाकार देश की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था या कोई अन्य महत्वपूर्ण हित का अतिलंघन होता है।

2. ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकार देश दूसरे संविदाकार देश को ऐसे पारगमन के बारे में अग्रिम नोटिस देगा।

**अनुच्छेद 15****लागत**

1. दंडदाता देश के अनन्य भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, इस करार को लागू करने में हुए किसी भी व्यय को निष्पादनकर्ता देश द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, निष्पादनकर्ता देश अंतरण की समस्त अथवा आंशिक लागत की दंडित व्यक्ति से अथवा अन्य किसी स्रोत से मांग नहीं करेगा अथवा उसे प्राप्त करना नहीं चाहेगा।

**अनुच्छेद 16****भाषा**

अनुरोध अथवा सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे अथवा उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद लगा होगा।

**अनुच्छेद 17****लागू होने का दायरा**

यह करार, इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दंड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

**अनुच्छेद 18****विवादों का निपटारा**

1. केन्द्रीय प्राधिकरण इस करार की व्याख्या इसके लागू होने या कार्यान्वयन से पैदा होने वाले किसी भी विवाद को परस्पर सुलझाने का प्रयास करेंगे।

2. यदि केन्द्रीय प्राधिकरण विवाद को परस्पर सुलझाने में समर्थ नहीं होते हैं तो इसे राजनयिक चैनलों के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

**अनुच्छेद 19****दंडित व्यक्तियों को सौंपा जाना**

1. दंडदाता देश द्वारा दंडित व्यक्ति को निष्पादनकर्ता देश को सौंपे जाने का स्थान वह होगा जिसके बारे में दंडदाता देश एवं निष्पादनकर्ता देश के बीच सहमति होगी। निष्पादनकर्ता देश दंडदाता देश से कैदी को ले जाने के लिए जिम्मेदार होगा तथा दंडदाता देश के क्षेत्र से बाहर दंडित व्यक्ति की अभिरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा।

**अनुच्छेद 20****संशोधन**

संविदाकार देशों द्वारा सहमत इस करार में कोई संशोधन अथवा आशोधन करार में उल्लिखित तरीके के अनुसार ही प्रभावी होगा।

**अनुच्छेद 21****अंतिम प्रावधान**

1. यह करार अनुसमर्थन के अधीन होगा। प्रत्येक संविदाकार देश, इस करार के लागू होने के लिए अपेक्षित इसकी कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित में यथाशीघ्र दूसरे संविदाकार देश को सूचित करेगा। यह करार अंतिम अधिसूचना की तारीख के दूसरे माह के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।
2. यह करार अनिश्चित अवधि के लिए लागू रहेगा। तथापि, इसे किसी भी संविदाकार देश द्वारा दूसरे संविदाकार देश को इसकी समाप्ति का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। इसकी समाप्ति ऐसे नोटिस की तारीख से छह महीने बाद प्रभावी होगी।
3. किसी भी परिसमापन के बावजूद, यह करार उन दंडित व्यक्तियों के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिन्हें इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया जा चुका है।

इस करार के साक्ष्य के रूप में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इस संबंध में विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसे बहरीन में वर्ष 2016 के माह जनवरी की तारीख 23 को हिन्दी, अंग्रेजी तथा अरबी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में तैयार किया गया है तथा इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं। व्याख्या में अंतर के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य

की सरकार की ओर से

बहरीन अधिराज्य

की सरकार की ओर से

[फा स. बी-17011/13/2013-पीआर]

डेनियल ई. रिचर्ड्स, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****CS DIVISION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2018

**G.S.R. 297(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Government of the Kingdom of Bahrain. The full text of the Agreement on Transfer of Sentenced Persons signed by the Government of Republic of India and the Government of the Kingdom of Bahrain on 23.1.2016 is given below. The Agreement was ratified by the Government of Republic of India on 10.3.2017 and by the Government of the Kingdom of Bahrain on 18.05.2017.

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS**

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Bahrain hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

Considering that this objective should be fulfilled by giving the nationals of the other Contracting State, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences in their own society;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1****Definitions**

For the purpose of this Agreement:

- (a) “judgment” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;

- (b) “executing State” means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof;
- (c) “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) “sentenced person” means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgment passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
- (e) “sentencing State” means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

## **ARTICLE 2**

### **General Principles**

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express in writing to the sentencing State or the executing State his willingness to be transferred under this Agreement.
2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the Government of that Contracting State

## **ARTICLE 3**

### **Central Authorities**

1. Central Authorities in charge of the implementation of this Agreement for the Contracting States are:
  - For the Republic of India: Ministry of Home Affairs.
  - For the Kingdom of Bahrain: Ministry of Justice, Islamic Affairs and Waqf.
2. In case either Contracting State changes its competent authorities, it shall notify the other State of the same through diplomatic channels.

## **ARTICLE 4**

### **Conditions for transfer**

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:
  - (a) the person is a national of the executing State;
  - (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
  - (c) the judgment is final;
  - (d) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the sentencing State in which his presence is required;
  - (e) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
  - (f) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment
  - (g) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the sentencing State are those which are punishable as a crime in the executing State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
  - (h) transfer of custody of the sentenced person to the executing State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other essential interest of the sentencing State;
  - (i) consent to the transfer is given in writing by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
  - (j) the sentencing and executing States agree to the transfer.
2. In exceptional cases, the sentencing and executing States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.



**ARTICLE 5****Obligation to furnish information**

1. If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing State in being transferred under this Agreement, the sentencing State shall send the following information and documents to the executing State unless either the executing or the sentencing State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person and his address, if any, in the executing State along with a copy of his passport or any other personal identification documents, and Fingerprints of the sentenced person, as possible;
- (b) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (c) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
- (d) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (e) a medical, social or any other report regarding the antecedents and character of the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
- (f) any other information which the executing State may specify as required, to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
- (g) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the sentencing State; and
- (h) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.
- (i) A statement from the sentencing State agreeing to the transfer of the sentenced person.

2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the executing State shall send the following information and documents to the sentencing State unless either the executing or the sentencing State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the executing State;
- (b) a copy of the relevant law of the executing State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the sentencing State constitute a criminal offence according to the law of the executing State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the executing State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 9 of this Agreement on his transfer;
- (d) the willingness of the executing State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
- (e) any other information or document which the sentencing State may consider necessary.

**ARTICLE 6****Requests and replies**

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed by the Central authority of the sentencing State through diplomatic channels to the Central Authority of the executing State. Replies shall be communicated through the same channels.

2. The executing State shall promptly inform the sentencing State of its decision whether to or not to agree to the requested transfer.

**ARTICLE 7****Consent and its verification**

1. The sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 4 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the sentencing State.

2. The sentencing State shall afford an opportunity to the executing State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

#### **ARTICLE 8**

##### **Effect of transfer for the executing State**

1. The competent authorities of the executing State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 9 of this Agreement.
2. Subject to the provisions of Article 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the executing State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

#### **ARTICLE 9**

##### **Continued enforcement of sentence**

1. The executing State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the sentencing State.
2. If the sentence is by its nature or duration, or both, incompatible with the law of the executing State, that State may, with the prior consent of the sentencing State, by court or administrative order, adapt the sentence to a sentence prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature and duration, the adapted sentence shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the sentencing State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the sentencing State.

#### **ARTICLE 10**

##### **Effect of completion of sentence for the sentencing State**

When the executing State notifies the sentencing state under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging the sentence in the sentencing state.

#### **ARTICLE 11**

##### **Review of judgment and Pardon, amnesty or commutation**

1. The sentencing State alone shall decide on any application for review of the judgment.
2. Either of the contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its constitution or other laws after consultation with the sentencing state.

#### **ARTICLE 12**

##### **Termination of enforcement of sentence**

1. The sentencing State shall promptly notify the Executing State of any decisions taken in its territory which entails terminating the enforcement of the sentence or part thereof.
2. The executing State shall terminate enforcement of the sentence or part thereof as soon as it is informed by the sentencing State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

#### **ARTICLE 13**

##### **Information on enforcement of sentence**

1. The executing State shall notify the sentencing State:
  - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
  - (b) If the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the executing State shall take measures to secure his arrest for the purposes of serving the remainder of his sentence and to render him/ her liable for committing an offence under the relevant law of the executing State.
2. The executing State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence.

#### **ARTICLE 14**

##### **Transit**

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit

- (a) if the sentenced person is one of its own nationals.
- (b) if the request may infringe upon the sovereignty, safety, public order or any other essential interest of the Contracting State.

2. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

#### **ARTICLE 15**

##### **Costs**

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the executing State, except costs incurred exclusively in the territory of the sentencing State. The executing State may not, however, demand or seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

#### **ARTICLE 16**

##### **Language**

Requests and supporting documents shall be in English or shall be accompanied by a translation into English.

#### **ARTICLE 17**

##### **Scope of Application**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

#### **ARTICLE 18**

##### **Settlement of Disputes**

- (1) The Central Authorities shall endeavour to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.
- (2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

#### **ARTICLE 19**

##### **Handing Over of Sentenced Persons**

The handing over of the transferred person by the sentencing State to the executing State shall occur at a place to be agreed upon between the sentencing and executing State. The executing State shall be responsible for the transport of the prisoner from the sentencing State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the sentencing State.

#### **ARTICLE 20**

##### **Amendments**

Any amendments or modifications to this Agreement agreed to by the Contracting States shall come into force in the same manner as the Agreement itself.

#### **ARTICLE 21**

##### **Final Provisions**

- 1. This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force on the first day of the second month of the date of the last notification.
- 2. The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the Contracting State by giving a written notice of termination to the other Contracting State. The termination shall take effect after six months of the date of such notice.
- 3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of prisoner who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

---

**In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.**

**Done in two originals at Bahrain on the 23rd day of January 2016, in the Hindi, English and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation the English text shall prevail.**

For the Government of  
the Republic of India

For the Government of  
Kingdom of Bahrain

\

[F.No. V-17011/13/2013-PR]

DANIEL E. RICHARDS, Jt. Secry.